



अनंत ज्ञान



चैत्र नवरात्र

षष्टम स्वरूप मां कात्यायनी

माता भगवती का छठा अवतार हैं कात्यायनी। इनकी पूजा छठे दिन की जाती है। छठे दिन साधक का मन आधा चक्र में स्थित रहता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी चार भुजाएँ हैं। दो हाथों में तलवार एवं कमल पुष्प सुशोभित हैं और दो हाथ वर और अक्षय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप, भय आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने मां भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा के सात वन में कठोर तपस्या की थी। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें पुत्री का वरदान दिया। इसके बाद महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए त्रिवेदी के तेज से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने असीम शक्ति और तेज के बल पर महिषासुर का अंत किया। कात्यायन गौत्र में जन्म लेने के कारण देवी भगवती कात्यायनी कहलाईं।

मंत्र : चंद्रहासो ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना। कात्यायनी शुभं दृष्यतिविव दानवघातिनी ॥

चिट्टा आरोपी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

प्रदेश कैबिनेट में नगर निकायों में डायरेक्ट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव अस्वीकृत

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। सोमवार सुबह हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन का निर्णय लेते हुए फैसला लिया है कि जो लोग चिट्टे के साथ पकड़े जाएंगे, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। पंचायत चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार इसके लिए राज्य विधानसभा में कानून पारित करने जा रही है। पारित विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही नया कानून अस्तित्व में आ जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 151 सीबीएसई स्कूलों में 2068 शिक्षकों को रखा जाएगा। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि मेडिकल कॉलेज



सचिवालय में मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू। अनंत ज्ञान

हमीरपुर, नरचौक और आईजीएमसी शिमला में बायो फिजिक्स विभाग को शुरू किया जाएगा। नाहन मेडिकल कॉलेज को शहर से बाहर बदलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में रखी गई। इस रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इसके बाद नाहन मेडिकल कॉलेज शहर से बाहर स्थानांतरित होगा। वहीं, हिमाचल प्रदेश में नगर पंचायत व नगर

प्रदेश के प्रमुख शहरों में पाइपों से गैस पहुंचाने पर निर्णय

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध पर भी चर्चा की गई। इसमें पाइपों से सभी प्रमुख शहरों के लिए घरेलू गैस को आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया। सभी पेट्रोलियम कंपनियों को इस बारे में सुविधाएं देने पर मंत्रणा हुई। विशेषकर भूमि अधिग्रहण के मामलों में पेट्रोलियम कंपनियों को सहयोग करने के मामले पर चर्चा हुई।

शहरी विकास विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा था, मगर यह योजना सिर नहीं चढ़ी, क्योंकि पूर्व की प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इस प्रयोग को कर चुकी है। उस दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी की नगर निगम शिमला के चुनाव में करारी हार हुई थी। उस अनुभव को देखते हुए डायरेक्ट चुनाव के प्रस्ताव को टाल दिया गया है।

अदालत पहुंचा गोहर में फैले पीलिया का मामला

अनंत ज्ञान

सुनील शर्मा, गोहर। गोहर उपमंडल में पीलिया के भयावह प्रकोप, दूषित पेयजल और खुले में बहते सीवरेज के मामले में बेहतर सौवरेज के मामले में आखिरकार अदालत ने सख्त रुख अपना लिया है। गोहर के सिविल जज कोर्ट ने सोमवार को बार एसोसिएशन गोहर द्वारा दायर जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सीपीसी की धारा 80(2) के तहत दायर आवेदन मंजूर कर लिया। अदालत के इस फैसले के बाद जलशक्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पंचायतों की कार्यप्रणाली अब सीधे न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। क्षेत्र

विश्राम गृहों की भोजन व सफाई व्यवस्था निजी एजेंसियों के हवाले

अनंत ज्ञान

इसके चलते यहां आने वाले अतिथियों और अधिकारियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है और उन्हें बाहर से इंतजाम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार टोस कदम उठा रही है, ताकि विश्राम गृहों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा।
♦ बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा ऐलाग
♦ बेहतर सुविधाएं देने के लिए लिया यह फैसला
अदालत के दवाजे तक पहुंच चुका है। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को दो दिन के भीतर विस्तृत स्टेटस तहत इन सेवाओं को प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन में अपने संबोधन के दौरान बताया कि लोक निर्माण, जल शक्ति और वन विभाग के कई विश्राम गृहों में वर्तमान समय में खाने-पीने और रख-रखाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

कैग रिपोर्ट में देरी, अतिरिक्त खर्च और नियमों की हुई अनदेखी एचपीएसआईडीसी में 100 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ियां उजागर

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में 100 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताएं और कार्यों में गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि कई परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी नहीं हो सकीं, जिससे संभावित राजस्व का नुकसान हुआ और सरकारी संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाया। जांच में पाया गया कि 44.96 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 परियोजनाएं बिना तकनीकी मंजूरी के ही शुरू कर दी गईं, जिनमें से 27.64 करोड़ रुपए का खर्च वर्षों पहले ही किया जा चुका था। वहीं, 103.40 करोड़ रुपए की दो प्रमुख आधारभूत परियोजनाएं तय समय के बाद भी अधूरी पड़ी हैं, जो कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 92 में से 33 कार्य समय पर पूरे नहीं हुए, जिससे एजेंसी शुल्क में 4.82 लाख रुपए का नुकसान हुआ और करीब 6.45 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कार्यों का अवसर भी हाथ से निकल गया। इसके अलावा परामर्श सेवाओं में 1.04 करोड़ रुपए और सेवा कर के रूप में 15.12 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जो वित्तीय अनुशासन की कमी को दर्शाता है।

शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1837 अंक टूटा

बैंकिंग, ऑटो, मेटल और एफएमसीजी शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज एजेंसी, सुबई

शेयर बाजार में 23 मार्च को बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 1837 अंक (2.46%) की गिरावट के साथ 72,696 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 602 अंक (2.60%) की गिरावट रही, यह 22,513 पर बंद हुआ। आज बैंकिंग, ऑटो, मेटल और एफएमसीजी शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। बाजार गिरने की 3 बड़ी वजहों में अमेरिका-

सोना 12 हजार और चांदी 31 हजार रुपए सस्ती

नई दिल्ली। अमेरिका-इसराइल की इरान से चल रही जंग के बीच सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 12,077 रुपए घटकर 1.35 लाख रुपए पर आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 40 साल में सोने के कीमत में इतनी

बड़ी गिरावट हुई है। इससे पहले इसकी कीमत 1.47 लाख थी। वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 30,864 रुपए घटकर 2.01 लाख रुपए पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को इसकी कीमत 2.32 लाख रुपए किलो थी। अमेरिका-इरान जंग के कारण सोना 24 दिन में 23,956 और चांदी 65,200 सस्ती हुई है।

डोनाल्ड ट्रंप ने इरानी पावर प्लांट्स पर हमला टाला

तेहरान/वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इरान के बीच पिछले दो दिनों से चली बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि रक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए रोक दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत सफल रहती है, तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इरान के ऊर्जा प्लांट्स पर पांच दिन तक हमले रोकने के निर्देश पर तेहरान ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को इरानी सरकारी टेलीविजन ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति इरान की कड़ी चेतावनी के बाद पीछे हट गए हैं। इरान ने धमकी दी थी कि अगर उसके पावर प्लांट पर हमला हुआ तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। (अनंत ज्ञान)

लोहारा में दादा ने चलाई गोली, पोता गंभीर जखमी

अनंत ज्ञान

बग्गी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के लोहारा गांव में रविवार रात पारिवारिक विवाद के दौरान सेवानिवृत्त फौजी बहादुर सिंह ने अपनी लाइसेंस बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसमें उसका पोता उमेश चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पहले नरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एम्स बिलासपुर रेफर किया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पुलिस को दी शिकायत में बहू मनीषा चौधरी (30) ने बताया कि उसके ससुर बहादुर सिंह अक्सर शराब के नशे में गली-गलीज और मारपीट करते हैं। रविवार शाम करीब 7:30 बजे भी वह नशे में मनीषा और उसके पति भूपेंद्र के साथ झगड़ा कर रहा था। विवाद बढ़ने पर बहादुर सिंह ने मनीषा पर बंदूक तान दी। शोर सुनकर जेट का बेटा (मनीषा का भतीजा) उमेश उन्हें बचाने पहुंचा, तभी आरोपी ने फायर कर दिया और गोली उमेश की दाईं कलाई को चीरते हुए उसके कुल्चे में लगी। फायरिंग के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई और मनीषा व उसके पति ने साहस कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी का इलाज एम्स बिलासपुर में पुलिस निगरानी में चल रहा है।

डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर 94.01 पर पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली। खाड़ी देशों में जारी इरान की जंग से आज रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपया डॉलर के 48 पैसे गिरकर मुकाबले 94.01 के स्तर पर बंद हुआ है। (अनंत ज्ञान)

टिप्पणी लोग सालों तक जेलों में सड़ रहे, यह विकसित भारत का आदर्श नहीं हो सकता

ज्यूडिशियरी हद से ज्यादा सख्त हो रही: जस्टिस भुइयां

एजेंसी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्वल भुइयां ने कहा कि ज्यूडिशियरी के कुछ हिस्से 'मोर लॉयल देन द किंग सिंड्रोम' से ग्रस्त हैं। यानी ये हिस्से राजा से भी ज्यादा बफादार होने की प्रवृत्ति अपना चुके हैं। इसके कारण ही लोग महीनों तक जेलों में सड़ते रहते हैं। जस्टिस भुइयां ने यह बात रविवार को बेंगलूर में हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली नेशनल सेंट्रल में कहा। 'विकसित भारत में न्यायपालिका की भूमिका' विषय पर पैनल डिस्कशन के दौरान जस्टिस भुइयां ने कहा- कुछ मामलों में सिस्टम इतना ज्यादा सख्त हो रहा है कि जबरूत से ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं।

कहा- पीएमएलए यूपीए एक्ट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल उनकी वैद्यु घटा रहा



अपनी स्पीच के दौरान जस्टिस भुइयां ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूपीए) जैसे कानूनों के तहत आरोपियों को लंबे समय तक हिरासत में रखे जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा- पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ऐसे मामलों से निपटने का एक बड़ा साधन है, लेकिन कानून का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल इसके असर को कमजोर करता है। वहीं, यूपीए को लेकर कहा कि जब दोषसिद्धि की दर लगभग 5% से भी कम है, तो आरोपी को सालों तक जेल में क्यों रखा जाए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े कुछ विवादों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी बनानी पड़ी है, जिससे सिर्फ समय की बर्बादी हुई है।

जस्टिस भुइयां ने कहा- 'विकसित भारत का आदर्श नहीं हो सकता' का विचार एक राजनीतिक लक्ष्य है और अदालतों को अपने कामकाज में स्वतंत्र रहना चाहिए। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो बहस और असहमति के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। असहमति को अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

जबरूत से ज्यादा इस्तेमाल पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया एक्टिविटी जैसे छोटे मुद्दों पर मनमाने ढंग से क्रिमिनल केस दर्ज किए जाने की निंदा की। पैनल डिस्कशन के दौरान जस्टिस भुइयां बोले- 'भारत में दलितों से भेदभाव जैसी सामाजिक दरारें बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं।

विकसित भारत राजनीतिक नारा, कोर्ट अलग रहें

जस्टिस भुइयां ने न्यायपालिका को विकसित भारत जैसे राजनीतिक नारों से बहुत ज्यादा जोड़ने के खिलाफ भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा- 'विकसित भारत' का विचार एक राजनीतिक लक्ष्य है और अदालतों को अपने कामकाज में स्वतंत्र रहना चाहिए। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो बहस और असहमति के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। असहमति को अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

माता-पिता यह ज़िद नहीं कर सकते कि बच्चे दलित महिला के हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे। हम ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकते जहां दलित पुरुषों, अनुसूचित जाति के पुरुषों को गलियारों में खड़ा किया जाए और लोग उन पर पेशाब करें। यह विकास का मॉडल नहीं हो सकता। व्यक्ति के सम्मान की रक्षा को जानी चाहिए।' (अनंत ज्ञान)

होर्मुज का रास्ता रोकना नामंजूर : प्रधानमंत्री मोदी

एजेंसी, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए। बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं हैं। होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। पीएम ने कहा कि संकट की घड़ी में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। अभी 3 लाख 75 हजार भारतीय सुरक्षित

अब 41 देशों से तेल व गैस इंपोर्ट कर रहे

पीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल-गैस संकट न हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में एक करोड़ भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने संकट के समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है। आज हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। इसे बढ़कर 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक करने का काम चल रहा है। हमारी तेल कंपनियां अलग स्टोरेज रखती हैं।

देश लौट चुके हैं। (अनंत ज्ञान)

विधानसभा की झलकियां

पेट्रोल-डीजल सेस पर सियासी टकराव, विपक्ष ने किया विरोध

प्रदेश में पेट्रोल व हाई स्पीड डीजल 5 रुपए तक महंगे होने के आसार

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त सेस लागू होने के बाद आम लोगों को जेब पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। नए प्रावधान के तहत प्रति लीटर अधिकतम 5 रुपए तक की बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है, जिससे राज्य में पहले से ऊंचे दाम और ऊपर जा सकते हैं। अनुमान है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्पष्ट उछाल दिखाई देगा।

दबाव बढ़ेगा। ईंधन महंगा होने का असर केवल वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि माल ढुलाई की लागत बढ़ने से सब्जियों, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। खास तौर पर टुक ऑपरेटर, टैक्सरी चालक व छोटे कारोबारी वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे महंगाई की शृंखला और तेज होने का संभावना है।

आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह फैसला राज्य के राजस्व को मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा सकता है, लेकिन उपभोक्ता स्तर पर इसका असर तुरंत व व्यापक होगा। पड़ोसी राज्यों के मुकाबले दाम बढ़ने से सीमा क्षेत्रों में ईंधन खरीद की प्रवृत्ति भी बदल सकती है, जिससे स्थानीय बाजार प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर आने वाले समय में हिमाचल में ईंधन की कीमतें महंगाई के नए दबाव के साथ एक बड़ा मुद्दा बन सकती हैं।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में पहले से ही पड़ोसी राज्यों की तुलना में ईंधन महंगा रहा है। ऐसे में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमतें कई क्षेत्रों में 105 रुपए प्रति लीटर के आसपास या उससे ऊपर पहुंच सकती हैं, जबकि डीजल भी 95 रुपए प्रति लीटर के करीब या उससे अधिक हो सकता है। इससे परिवहन, खेती-बाड़ी और रोजमर्रा के खर्चों पर सीधा



बजट सत्र में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू को पुलिस जवान सलामी देते हुए।



बजट सत्र में शामिल होने से पहले डिप्टी चीफ क्लर्क केवल पटानिया ने मुख्यमंत्री सुक्खू का स्वागत किया।



सदन की कार्यवाही आरंभ होने से पूर्व कृषि मंत्री चंद्र कुमार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमसिंह सिंह के साथ शिष्टाचार भेंट करते विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटानिया।

सीएम बोले-सेस से प्राप्त राशि अनाथ और विधवाओं के कल्याण के लिए होगी इस्तेमाल

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। हिमाचल विधानसभा में पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए सेस को लेकर जोरदार सियासी टकराव देखने को मिला। इस मुद्दे पर सदन के भीतर तीखी बहस हुई और विपक्ष ने सरकार के फैसले का खुलकर विरोध किया। माहौल इतना गरमाया कि भाजपा विधायक विरोध जताते हुए सदन से बाहर भी निकल गए।

विपक्ष का कहना था कि इस सेस का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल महंगे होने से परिवहन खर्च बढ़ेगा, जिससे बस किराया, सोमेट की ढुलाई और खाद्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे। इस तरह यह फैसला



पेट्रोल-डीजल सेस लगाने के खिलाफ वॉकआउट के बाद मीडिया के बात करते भाजपा नेता।

आम लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डालने वाला साबित होगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि यह सेस सरकार चलाने के लिए नहीं बल्कि अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है और विपक्ष को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

सदन में गुंजा तबादला मुद्दा, आपसी सहमति से ट्रांसफर का प्रावधान नहीं

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकारी सेवा में आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी तबादले निर्धारित नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं और जनहित को ध्यान में रखते हुए ही किए जाते हैं, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और संतुलन बलादी।

मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि पिछले छह महीनों में कुल 1171 कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। इनमें कुछ मामलों में संबंधित कर्मचारियों की आपसी सहमति भी सामने आई, लेकिन इन तबादलों को भी केवल सहमति के आधार पर नहीं, बल्कि प्रचलित नियमों और तय मानकों के अनुरूप ही अमल में लाया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य

- ◆ सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया सरकार का रुख
- ◆ नीति व प्रशासनिक जरूरतों पर ही होंगे तबादले
- ◆ 6 माह में 1171 कर्मचारियों के हुए स्थानांतरण

किसी भी प्रकार की मनमानी को रोकते हुए सुव्यवस्थित प्रशासन सुनिश्चित करना है। सदन में यह भी स्पष्ट किया गया कि कर्मचारियों द्वारा दिए गए आपसी स्थानांतरण के आवेदन पत्रों पर सरकार विचार जरूर करती है, लेकिन प्रत्येक मामले को गुण-दोष, पदों की उपलब्धता और विभागीय जरूरतों के आधार पर परखा जाता है। सरकार का मानना है कि तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह नीति आधारित रखना ही कर्मचारियों और जनता दोनों के हित में है, ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली प्रभावो और निष्पक्ष बनी रहे।

हर साल 1 लाख रोजगार का वादा सवालियों में विधानसभा में रोजगार मुद्दे पर गरमाई बहस, जयराम ने 15 हजार पद घटने का लगाया आरोप

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में रोजगार का मुद्दा जोरदार तरीके से गुंजाता रहा और प्रश्नकाल के दौरान यह विषय केंद्र में बना रहा। विभिन्न विभागों से जुड़े सवालियों के बीच विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए प्रदेश में रोजगार की स्थिति पर गंभीर प्रश्न उठाए। सदन का माहौल इस मुद्दे को लेकर काफी गर्म रहा और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आंकड़ों का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश में स्थायी नौकरियों की संख्या 1,90,137 थी, जो अब घटकर 1,75,579 रह गई है। उनके अनुसार मौजूदा सरकार



के कार्यकाल में करीब 15 हजार नौकरियों कम हुई हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने हर साल एक लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को सवालियों के साथ विश्वासघात करार देते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब

रोजगार सृजन की आवश्यकता है, तब पदों में कमी होना प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक संकेत नहीं है। विपक्षी सदस्यों ने यह भी कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है, लेकिन सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने में असफल नजर आ रही है। वहीं, सरकार की ओर से इस विषय पर दिए गए जवाबों को विपक्ष ने असंतोषजनक बताया, जिसके चलते सदन में बहस और तेज हो गई। दोनों पक्षों के बीच कई बार तीखी बहस हुई, जिससे सदन का वातावरण गरमाता रहा। कुल मिलाकर, बजट सत्र के दौरान रोजगार का मुद्दा सबसे प्रमुख बनकर उभरा और इस पर हुई बहस ने प्रदेश की राजनीति में नई गरमाहट पैदा कर दी है।

बजट में कटौती पर विपक्ष का हमला, विकास पर उठे सवाल

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। विधानसभा में बजट अनुमान पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को विभिन्न विभागों में बजट कटौती को लेकर घेरा। सदन में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें विकास कार्यों पर संभावित असर को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। विपक्ष ने इसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति का संकेत बताते हुए गंभीर मुद्दा बताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कृषि विभाग में 34.39 प्रतिशत, ग्रामीण विकास में 52.12 प्रतिशत और वेलफेयर सेक्टर में 62.63 प्रतिशत तक बजट में कमी आई है। उन्होंने कहा कि यदि कुल बजट को देखा जाए तो महत्वपूर्ण विभागों में लगभग 42 प्रतिशत तक कटौती की गई है, जो विकास कार्यों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट का आकार बढ़ने के बजाय कम हुआ है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार संसाधनों की कमी को छुपाने की कोशिश कर रही है और वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखा जा रहा है।

600 से अधिक पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू : नेगी

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। विधानसभा में राजस्व विभाग से जुड़े प्रश्न के दौरान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम जानकारी साझा की। भले समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद जताई गई।

- ◆ कहा- लंबे समय से खाली पदों से प्रभावित हो रहा था कामकाज
- ◆ ट्रांसफर पॉलिसी को कानून का रूप देने पर सरकार का विचार

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश में 600 से अधिक पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में इन पदों पर भर्ती नहीं हो सकी, जिसके कारण कई क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हो रहा था। अब नई भर्ती के माध्यम से इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे राजस्व से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि भर्ती किए जाने वाले पटवारियों

को ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें संबंधित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, ताकि लोगों को समय पर सेवाएं मिल सकें। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने संकेत दिए कि भविष्य में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कानून बनाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे तबादलों की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार आएगा।

हिमाचल पुलिस के 15 कर्मियों को मिला स्टार परफॉर्मर अवार्ड

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने कर्तव्य के प्रति उत्कृष्ट समर्पण और सराहनीय कार्य के लिए 15 पुलिस कर्मियों को 'स्टार परफॉर्मर अवार्ड' से सम्मानित किया है। इस सूची में सब-इंस्पेक्टर सरदार सिंह, रणधीर सिंह, बशीर मोहम्मद, एएसआई विनय कुमार और गुरजीत सिंह सहित हेड कांस्टेबल सावन, विजय सिंह, कृष्णा तथा कांस्टेबल अतुल ठाकुर, नीतू भारद्वाज, महिला कांस्टेबल शालिनी, आरती, आशा, गायत्री देवी और सुशील कुमार शामिल हैं। खास बात यह रही कि सम्मानित कर्मियों में पांच महिला पुलिसकर्मियों ने भी अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से अलग पहचान बनाई। पुलिस विभाग के अनुसार इन कर्मियों ने अपराध नियंत्रण, चिट्ठा बरामदगी और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विभाग का मानना है कि इस तरह के सम्मान से पुलिस बल में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और कर्मियों का मनोबल ऊंचा होता है, जिससे आम जनता के बीच पुलिस की विश्वसनीयता और मजबूत होती है।

शांडिल और नेगी ने की बजट की प्रशंसा दोनों ने प्रदेश के बजट को बताया दूरदर्शी और जनकल्याणकारी

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, शिमला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को दूरदर्शी, सशक्त और जनकल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि यह कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के समग्र विकास को मजबूत आधारशिला रखता है। उन्होंने कहा कि केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान में भारी कटौती के कारण लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने संतुलित और प्रगतिशील बजट पेश कर विकास की गति को बनाए रखने का भरपूर साया दिया है।

मंत्रियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रावधानों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि 3,000 करोड़ रुपये से आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा और चिकित्सा अधिकारियों व स्टाफ नर्सों सहित हजारों पदों को

पुलिस, स्वास्थ्य में भर्तियों का मार्ग प्रशस्त



'आत्मनिर्भर हिमाचल' की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और आर्थिक दबावों के बावजूद प्रदेश की विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ती

मंत्रियों ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर देते हुए पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भर्तियों का मार्ग प्रशस्त किया गया है तथा रोजगार योजनाओं के माध्यम से 4 लाख मानव-दिवस सृजित किए जाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह बजट राजस्व चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी को कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद हर वर्ग का ध्यान रख रही है।

भरा जाएगा। सीनियर रजिस्ट्रार स्पेशलिस्ट और सुपर-स्पेशलिस्ट के स्ट्राइपेंड में वृद्धि से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी। इसके साथ ही डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों को मजबूत बनाने पर दिया गया जोर दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाने की दिशा में अहम कदम है। राजस्व मंत्री नेगी ने कहा कि बजट में राजस्व विभाग

के पूर्ण डिजिटलीकरण का निर्णय आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। भूमि अभिलेखों और म्यूटरेशन प्रक्रियाओं को सरल बनाने से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक जटिलताएं खत्म होंगी। उन्होंने राजस्व चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी को कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद हर वर्ग का ध्यान रख रही है।

मंथन विद्यार्थियों पर बढ़ते आर्थिक बोझ पर सतर्क हुई सरकार, सदन में मुद्दे पर गरमाई चर्चा, पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

सरकारी स्कूलों के छात्रों को हिम बस कार्ड में रियायत देने पर विचार

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को हिम बस कार्ड बनवाने में राहत देने के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठे इस विषय ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका जताई जा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार इस व्यवस्था की समीक्षा करेगी, ताकि विद्यार्थियों को अनावश्यक कठिनाई न हो। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान धर्मशाला से विद्यार्थी सुधीर शर्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम की बसों में

महिलाओं को किराये में रियायत से निगम पर बढ़ा वित्तीय बोझ

उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि महिलाओं को बस किराये में दी जा रही 50 प्रतिशत रियायत के कारण परिवहन निगम पर अब तक 82 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। प्रति माह औसतन 37 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं, जबकि बीते एक वर्ष में लगभग पांच करोड़ महिलाओं ने इस सुविधा का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि हिम बस कार्ड के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों का सही आंकड़ा सामने आएगा, जिससे सब्सिडी के प्रबंधन में भी पारदर्शिता आएगी।

रियायती तथा निशुल्क यात्रा का लाभ लेने के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में लगभग दो लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं, लेकिन इतने ही हिम बस कार्ड बनवाने से विद्यार्थियों पर पड़ रहे अतिरिक्त भार को लेकर सरकार सजग है और आवश्यक सुधारों पर विचार किया जा रहा है। नई व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थियों को निशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए पहले 236 रुपये खर्च कर हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त लोकमित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर 40 रुपये शुल्क भी देना पड़ रहा है।

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पहली से बारहवीं कक्षा तक लगभग साढ़े आठ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें से बड़ी संख्या योजना बसों के माध्यम से विद्यालय पहुंचती है। ऐसे में यह अतिरिक्त खर्च अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इस दौरान सदन में राजनीतिक नोकझोंक भी देखने को मिली। सुधीर शर्मा ने कहा कि जब तक महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक इस तरह की अनिवार्यता उचित नहीं है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार की पूर्व घोषणाओं पर सवाल उठाए, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सदन में यह मुद्दा कुछ समय तक चर्चा का केंद्र बना रहा।

महिलाओं के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य, 31 मार्च अंतिम तिथि

अनंत ज्ञान

सत्यदेव भारद्वाज, शिमला। प्रदेश में सरकारी बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सदन में विस्तृत जानकारी दी गई और इसे व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि कई बार अन्य राज्यों के लोग भी इस सुविधा का लाभ लेते

बाहरी यात्रियों की पहचान के लिए लिया फैसला

हैं, इसलिए पहचान सुनिश्चित करना जरूरी हो गया था। इसीलिए सभी महिलाओं के लिए कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया है। सरकार के अनुसार अब तक 2 लाख से अधिक हिम बस कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक कार्ड बनवाना जरूरी है, हालांकि अंतिम तिथि को लेकर नीतिगत स्तर पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल सरकार समयसीमा के भीतर अधिक से अधिक कार्ड बनाने पर जोर दे रही है।

सीनियर सिटीजन काउंसिल चुनाव में वोटर लिस्ट को किया दरकिनार

चुनाव अधिकारी ने हाजिरी रजिस्टर के आधार पर करवाए चुनाव

अनंत ज्ञान

अनिल कुमार, हमीरपुर। बेशक सीनियर सिटीजन काउंसिल का गठन अर्द्धाई दशक पहले मरीजों खाना देने के लिए किया गया था, लेकिन 22 मार्च को पहली बार बड़े स्तर पर करवाए गए संस्था के चुनावों से इसका ध्येय मरीजों की सेवा से पीछे छूटता जा रहा है।

जिस समय यह संस्था बनाई गई थी उस समय कई मुश्किलों का सामना करते हुए मरीजों को दलिया देने का कार्य शुरू किया था। फिर इस संस्था में लोग जुड़ते गए और आर्थिक तौर पर भी संस्था की मदद करने के लिए लोग आगे आने लगे। आर्थिक सहायता अने के बाद अस्पताल में दाखिल मरीजों को खाना देने के बारे में विचार किया, उसके बाद लगभग अर्द्धाई दशक से यह संस्था उपरोक्त को तीन समय से खाना उपलब्ध करवा रही है। इस संस्था को 5 हजार से अधिक

हाजिरी रजिस्टर पर विवाद के कारण चुनाव रद्द, उपायुक्त के आदेश का इंतजार



कि चुनाव संस्था को करवाने हैं और प्रशासन की ओर से केवल सही तरीके चुनाव करवाने की जिम्मेदारी थी। आर्जनर तहसीलदार नरेश पटेलवाल ने बताया कि मेरा काम सही तरीके चुनाव करवाने की निगरानी रखना था। उन्होंने बताया कि चुनावों से संबंधित रिपोर्ट चुनाव अधिकारी ही देंगे।

दानकर्ता परिवार अपना सहयोग दे रहे हैं और बीमारी से ठीक होकर घर जाने वाला मरीज भी कुछ न कुछ दान करते हैं। कथित कुछ माह पहले संस्था में सेवा करने के लिए आने वालों के साथ संस्था को पदाधिकारियों का विवाद हो गया। जब यह बात प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन ने जांच करने के बाद इस संस्था में सदस्यता बढ़ाने और चुनाव करवाने का आदेश संस्था के

चुनाव अधिकारी ने हाजिरी रजिस्टर पर चुनाव करवाए, जबकि जो सदस्यों की लिस्ट और आईडी कार्ड जारी किए गए। इस आधार पर वोट डाले जाने चाहिए थे, लेकिन हाजिरी रजिस्टर पर चुनाव करवाए, जिस पर विवाद हुआ और चुनाव को रद्द करना पड़ा। हालांकि, चुनाव अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट उपायुक्त हमीरपुर गंधर्वा राठौड़ को सौंप दी है। अब इसके बाद उपायुक्त द्वारा आगामी आदेश जारी किए जाएंगे। यह चुनाव करवाने के आदेश एसडीएम हमीरपुर संजैत ठाकुर ने संस्था को दिए थे। उन्होंने बताया

पदाधिकारियों को दिया। संस्था के पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान चलाया और कुल 328 सदस्य इससे जुड़े। यह चुनाव रविवार 22 मार्च को करवाया, जिसके लिए प्रशासन की ओर से चुनाव अधिकारी व पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। प्रधान दल के लिए वोट भी डाले गए, लेकिन हाजिरी रजिस्टर में वोट रबढ़ने को लेकर विवाद हो गया। हाजिरी रजिस्टर से

भी अधिक सदस्य वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। चुनाव अधिकारी ने वोटिंग बंद कर दी और जो वोट डाले गए थे उन्हें सील कर अपने साथ ले गए। इसके साथ हाजिरी रजिस्टर और सारा रिर्काई अपने साथ ले गए। अधिकतर बुद्धिजीवियों ने चुनाव अधिकारी द्वारा करवाए गए इस चुनाव को गलत ठहराया है।

सीनियर सिटीजन काउंसिल के चुनाव में प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप अशुभ संकेत : जोगिंद्र

अनंत ज्ञान, हमीरपुर। जिला मुख्यालय पर दशकों से समाज सेवा और कल्याण कार्यों में अग्रणी संस्था सीनियर सिटीजन काउंसिल के चुनाव में अनापेक्षित गहमागहमी और फिर चुनाव का स्थगित होना न केवल संस्था के लिए बल्कि समाज सेवा में संलग्न तमाम संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए एक चिंता का विषय तो है, ही साथ ही सेवा क्षेत्र के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। यह बात राजपूत महासभा के महासचिव जोगिंद्र ठाकुर ने जारी प्रेस बयान में कही। उन्होंने कहा कि ये संस्था जिले के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान में वर्षों से मरीजों और उनके किमार्शदों को तीन समय का भोजन उपलब्ध करवाती है। वहीं, जरूरतमंदों को निशुल्क दवाइयां प्रदान करने के साथ ही समाजसेवा के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। संस्था को जिले के सैकड़ों वरिष्ठ नागरिक रोज़ेछ से योगदान देते हैं, इस गहमागहमी का कारण कहीं इसकी संपत्ति और नकदी पर कोई गिद्द नजर तो नहीं है। इस संस्था को न केवल जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में प्रतिष्ठित संस्था के रूप में अनुकरणीय माना जाता है। इसमें पिछले कल जो प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिले व न केवल सेवा क्षेत्र के लिए अशुभ संकेत है, बल्कि इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए हतोत्साहित करने वाला था। संस्था वर्षों से बेहतरीन कार्य कर रही है, जो सरकारें कभी न कर पाई वह भी कर दिखाया है। सरकार, प्रशासन और सभी राजनीतिक दल इसमें अनावश्यक दखल देती हैं। संस्था को प्रोत्साहित करे, ताकि ये सेवा का सिलसिला लगातार जारी रहे। निस्वार्थ सेवा के लिए किसी प्रशासनिक दखल की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह की घटना अति दुर्भाग्यपूर्ण है संस्था के सभी सदस्यों को सभी राजनीतिक या निजी महत्व अकांक्षाओं को छोड़कर सत्यसम्मति से सेवा भाव से कार्य करने वालों को चुनकर इस मान्यता की सेवा के पुनीत कार्य को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर होना ही सबसे बड़ा त्याग और समर्पण का कार्य होगा।

नादीन उपमंडल के कई गांवों में तीन सप्ताह से रसोई गैस की आपूर्ति नहीं



अनंत ज्ञान, नादीन। नादीन उपमंडल के कई गांवों के लोग रसोई गैस न मिलने की वजह से परेशान हैं। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी नादीन के अध्यक्ष देशराज दड़ोच ने रसोई गैस की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पर ऑनलाइन शिकायत करते हुए कहा कि टीका जड़ौत के गांव मलानकड़, भदरोल, झगड़वाल, भलू, कुठारली व जड़ौत में पिछले तीन सप्ताह से इंडेन गैस के सिलेंडर की सप्लाई नहीं हुई है। इस वजह से लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रसोई गैस की सिलेंडर सप्लाई करने वाली गाड़ी वाले दूरदराज के गांव में एक ही जगह गाड़ी खड़ी करके अपने रिश्तेदारों व दोस्तों को बुलाकर एक ही जगह पर गैस की सप्लाई दे रहे हैं। इसके चलते रसोई गैस की गाड़ी गंतव्य तक पहुंचने की बजाय पीछे से ही वापस हो जाती है। उन्होंने कहा कि पहले रसोई गैस की सप्लाई हर शनिवार को आती है, लेकिन पिछले तीन सप्ताह से नहीं आ रही है। गैस सप्लाई वाले मनमानी कर रहे हैं पूरा इलाका परेशान है प्रशासन से आग्रह किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उपरोक्त गांव में सीकर रसोई गैस की सप्लाई उपलब्ध करवाई जाए।

डीएवी स्कूल भड़ोली ने किया वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित



प्रधानाचार्य सुरजीत ने विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। अनंत ज्ञान

अनंत ज्ञान

नादीन। डीएवी पब्लिक स्कूल भड़ोली में कक्षा एलकेजी से कक्षा दूसरी तथा कक्षा ग्यारहवीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रधानाचार्य सुरजीत कुमार राणा के निर्देशन में घोषित किया गया। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय का परिणाम शत-प्रतिशत रहा। ग्यारहवीं कक्षा में अंतरिक्ष वर्मा ओवरऑल टॉपर रहे।

नाॅन-मेडिकल संकाय में प्रथम स्थान अंतरिक्ष वर्मा, द्वितीय सुचित भाटिया और तृतीय प्रंजल शर्मा ने प्राप्त किया। मेडिकल संकाय में प्रथम अर्णव कुमार, द्वितीय प्रज्ञ दत्त और तृतीय तेजस शर्मा रहे। कक्षा

एलकेजी और यूकेजी से टॉप 10 में वैष्णवी जन्माल, सनाया, शनाया प्रीथी, अनन्या शर्मा, शरण्या शर्मा, प्रांशु डोगरा, सात्विक सोनी, दिव्यांश, अद्वैत, आध्वन सहित अन्य विद्यार्थियों का नाम शामिल है। कक्षा प्रथम और कक्षा द्वितीय के मेधावी छात्रों की सूची में भी प्रत्येक कक्षा से 10-13 शीर्ष छात्र शामिल किए गए हैं, जिनमें अनिका, कायरा, अन्याय, शारविल, प्रज्ञा शर्मा, कार्तिकेय राणा, आयुष रेकड़ा, शौर्य ठाकुर, रंश, अनन्या, शिवांश राणा आदि शामिल हैं। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को भविष्य की पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं दीं।

बैठक डीसी ने एचआईवी-एड्स प्रभावितों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश

लोगों और आश्रितों तक पहुंचाएं योजनाएं



समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करती डीसी गंधर्वा राठौड़। अनंत ज्ञान

अनंत ज्ञान

हमीरपुर। जिले में एचआईवी-एड्स से प्रभावित लोगों के लिए आयोजित वार्षिक समीक्षा बैठक में उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए।

हमीर भवन में आयोजित बैठक में कहा कि सभी मरीजों को एआरटी सेंटर के माध्यम से नियमित रूप से दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी

मिले। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि एचआईवी-एड्स से ग्रस्त लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और उनकी पहचान गोपनीय रखी जाए। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर में स्थापित एआरटी सेंटर के माध्यम से हमीरपुर सहित बिलासपुर, मंडी, ऊना और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों के कुल 1453 मरीजों को दवाइयों उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिनमें 953 मरीज हमीरपुर जिले से हैं। उन्होंने जागरूकता को सबसे प्रभावी

घरेलू गैस कनेक्शन धारकों के लिए हो रही है पर्याप्त आपूर्ति, अफवाहों पर ध्यान न दें

अनंत ज्ञान, हमीरपुर। हमीरपुर जिले में उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने विभिन्न विभागों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ रसोई गैस आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 10 एजेंसियों के माध्यम से 1,63,343 घरेलू और 3339 व्यावसायिक कनेक्शनधारकों को गैस उपलब्ध करवाई जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति होने के कारण अफवाहों से बचने और निर्धारित अवधि (25 दिन, दरदराज क्षेत्रों में 45 दिन) के अनुसार बुकिंग करने की सलाह दी गई। हालांकि व्यावसायिक सिलेंडरों की कमी को देखते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। स्कूलों और अस्पतालों को विशेष छूट दी गई है, जबकि अन्य संस्थानों को वैकल्पिक ईंधन अपनाने को कहा गया। बैठक में जिला नियंत्रक शिव राम ने स्थिति की विस्तृत जानकारी दी।

बचाव बताते हुए कहा कि युवाओं में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं का एचआईवी टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है ताकि समय रहते उपचार शुरू कर शिशु को संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि वे फील्ड में जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाएं और रेड रिबन क्लबों को

सक्रिय रखें, ताकि समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके। बैठक में सीएमओ डॉ. प्रवीण चौधरी, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमएस डॉ. देशराज शर्मा और जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी सुनील वर्मा ने विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

स्मार्ट मीटर और बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में किया प्रदर्शन

अनंत ज्ञान

नादीन। नादीन के गांव सलोह, लाहड़ और बोंहड़ में आयोजित बिजली उपभोक्ताओं की बैठक में विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा, रमेश चंद, अजीत कुमार सहित लगभग 150 लोगों ने भाग लिया। बैठक में स्मार्ट मीटर लगाने का पुरजोर विरोध किया गया और सरकार से इसकी प्रक्रिया को तुरंत बंद करने की मांग की गई।

प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 बिजली वितरण क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम है। यह विधेयक राज्यों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि देश और प्रदेश के विद्युत कर्मचारियों ने शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित किया और विशाल बिजली ढांचा तैयार किया, फिर भी अब मीटर

नादौन में बिजली उपभोक्ताओं ने की बैठक

लगाने, बदलने और बिल जनरेट करने जैसे कार्य निजी कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं। खरवाड़ा ने सवाल उठाया कि 9 साल बाद क्या यह नियंत्रण फिर से सरकारियों विद्युत बोर्ड लिमिटेड को मिलेगा या स्थायी रूप से निजी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग के फायदे केवल

निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रचारित किए जा रहे हैं जबकि कुछ अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी रूप से कर्मचारियों और पेंशनरों के घरों में प्राथमिकता के आधार पर मीटर लगाए जा रहे हैं। बैठक में सभी उपस्थित लोगों ने सरकार से अपील की कि स्मार्ट मीटरिंग प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए, बिजली संशोधन विधेयक 2025 के लागू होने से पहले कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और पेंशनरों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

अनुराग ने पीएम नरेंद्र मोदी को 25 वर्ष पूर्ण करने पर दी बधाई

अनंत ज्ञान, हमीरपुर। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूर्ण करने और पूर्व सिकंदर मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिर्काई पार करने पर बधाई दी। 8,931 दिनों के कार्यकाल के साथ, प्रधानमंत्री मोदी देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सरकार प्रमुख बन गए हैं। अनुराग ने इसे प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता, राष्ट्रभक्ति और जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री के पश्चिम एशिया संकट पर संसद में दिए गए व्यापक और समयोचित संबोधन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा, ऊर्जा आवश्यकताओं और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों, विशेषकर होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने संवाद और कूटनीतिक के माध्यम से संकट समाधान की दिशा में किए गए प्रयासों की जानकारी दी। अनुराग ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्कीमिटी और अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। ऊर्जा आयात को विविधीकृत किया गया, फेरलू एलपीजी व ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की गई, और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा एवं मदद के लिए विशेष कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि भारत इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक करेगा और समाज के सभी वर्ग सतर्क एवं एकजुट बने रहें।

दियोटसिद्ध में उमड़ा आस्था का सैलाब

अनंत ज्ञान, बड़सर। बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चल रहे चैत्र मेलों के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था अपने चरम पर है। सोमवार को हुई चढ़ावे की गणना में श्रद्धालुओं ने बाबा जी की पवित्र गुफा में दिल खोलकर भेंट अर्पित की। मंदिर प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार को कुल 9,70,205 रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। इसमें श्रद्धालुओं द्वारा नकद चढ़ावे के रूप में 18,33,305 रुपए अर्पित किए गए, जबकि डोनेशन के रूप में 749900 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त बकरों की नीलामी से भी न्यास प्रशासन को 3,87,900 रुपए की आय हुई है। चढ़ावे में नकदी के साथ-साथ बहुमूल्य धातुएं भी शामिल हैं। श्रद्धालुओं ने 2 ग्राम 220 मिलीग्राम सोना तथा 11 ग्राम 890 मिलीग्राम चांदी भी अर्पित की। इसके अलावा विदेशी मुद्रा के रूप में 240 इंग्लैंड पाउंड, 815 अमेरिकी डॉलर, 10 यूरो, कनाडा डॉलर 630, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 105, यूईरिहम10 भी चढ़ावे में शामिल हैं।

नशे के खिलाफ जन आंदोलन में दें योगदान : नरेश राज राजेशवरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



प्रतिभागियों ने नशा विरोधी रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। अनंत ज्ञान

अनंत ज्ञान

भोटा। राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर ने कहा कि नशे की तस्करी में संलग्न नेटवर्क को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने व्यापक अभियान छेड़ा है। उन्होंने युवाओं और समाज के सभी वर्गों से इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया, ताकि हिमाचल प्रदेश को नशामुक्त बनाया जा सके।

राज राजेशवरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में नरेश ने कहा कि युवा

खी जाती है। नरेश ने बताया कि सरकार नशा निवारण एवं उपचार केंद्रों को सुदृढ़ कर रही है और जाल सफाई में नए मेंडिकल कॉलेज परिसर में बड़ा नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल गतिविधियों के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रबंधन भी किया गया है। कार्यक्रम में रूबल सिंह ठाकुर, डॉ. राज धीमान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में प्रतिभागियों ने नशा विरोधी रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया।

एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर की नवीनतम तकनीकों पर की चर्चा

एचपी इस्कॉन 2026 राज्य सम्मेलन संपन्न



डॉ. आरकेएमसी हमीरपुर में एचपी इस्कॉन का आयोजन। अनंत ज्ञान

अनंत ज्ञान

हमीरपुर। डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के अध्यक्ष एनेस्थीसिया विभाग द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स का वार्षिक राज्य सम्मेलन 'एचपी इस्कॉन 2026' सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल प्रो. डॉ. रमेश भारती की गरिमामयी उपस्थिति रही। सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स, फैंकल्टी और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने भाग लिया। वैज्ञानिक कार्यक्रम में कीनो

लेक्चर, पैनेल चर्चा, केस-आधारित सत्र और हैंड्स-ऑन वर्कशॉप आयोजित किए गए, जिनमें एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर और दर्द प्रबंधन की नवीनतम तकनीकों पर चर्चा हुई। प्रो. वीरेंद्र के. आर्य (कनाडा), ने ट्रांस थोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी में विशेष सहभागिता दी। आयोजन समिति में डॉ. मनजीत सिंह कंवर, डॉ. प्रियंका सूद, डॉ. पूजा ठाकुर, डॉ. निशा शर्मा, डॉ. नीरज शर्मा और डॉ. भावना अहलुवालिया शामिल रहे। सम्मेलन का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ और आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

चलोटीधार की ऊंचाइयों पर विराजती सुरगणी माता

'बारिश की देवी' के रूप में पूजनीय माता के मंदिर में वर्षभर लगा रहता है श्रद्धालुओं का आना-जाना

अनंत ज्ञान

अभिषेक शर्मा, जोगिंद्रनगर। पांचवें चैत्र नवरात्रि में उपमंडल जोगिंद्रनगर के अंतर्गत चलोटीधार की ऊंची पहाड़ी पर स्थित सुरगणी माता का भव्य एवं प्राचीन मंदिर क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में अपनी विशेष पहचान रखता है। 'बारिश की देवी' के रूप में पूजनीय माता सुरगणी के इस मंदिर में वर्षभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है। प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस पवित्र स्थल पर पहुंचकर भक्त न केवल आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं।

बताया जाता है कि प्राचीन समय में त्रैलोक्यी पंचायत के झा गांव के समीप स्थित गुफाओं में एक महात्मा निवास करते थे। उनके साथ गद्दी समुदाय के लोग और एक बालक भी रहता था। एक दिन उस बालक को स्वप्न में संकेत मिला कि महात्मा उसे बुला रहे हैं। स्वप्न के अनुसार जब बालक

माता के चरण चिन्ह आज भी हैं आस्था का प्रतीक



महात्मा के पास पहुंचा, तो महात्मा ने पहाड़ी से एक चिमटा नीचे गिराया और उसे लाने के लिए कहा। बालक जैसे ही चिमटा लेकर वापस लौटा और ऊपर पहाड़ी की ओर देखा,

तो उसने एक चमकरी दृश्य देखा। रात का समय होते हुए भी वहां दिन जैसा प्रकाश फैला हुआ था और पहाड़ी पर लाल साड़ी में सजी तीन दिव्य देवियों प्रकट हुईं। यह दृश्य देखकर बालक आश्चर्यचकित रह गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये तीनों देवियां सुरगणी माता, भगवती माता और चतुर्भुजा माता के स्वरूप थीं। उसी स्थान के समीप उनके चरणों के निशान भी दिखाई दिए, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं।

चलोटीधार की पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर चारों ओर से हरियाली और शांत वातावरण से घिरा हुआ है। यहां पहुंचने पर श्रद्धालुओं को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। मंदिर परिसर से आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम नजारा भी देखने को मिलता है, जो इसे धार्मिक के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है।

सुरगणी माता मंदिर प्रबंधन कमिटी के सचिव राकेश राणा ने बताया कि यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

न्यूज ब्रीफ

कल बिल जमा न किया तो कटेगा कनेक्शन

अनंत ज्ञान, पंडोह। विद्युत विभाग अब सख्त हो गया है। बिजली के बकाया बिल की अदायगी ना करने वालों के विद्युत कनेक्शन हमेशा के लिए कट सकते हैं। पंडोह उप मंडल के सहायक अभियंता संजय कुमार ने बताया कि पंडोह क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से निवेदन किया है कि सभी 25 मार्च तक अपने बकाया बिल की अदायगी कर लें। अन्यथा आपके कनेक्शन कट जायेंगे। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

मंडी में शहीदों के बलिदान पर डाला प्रकाश



अनंत ज्ञान ब्यूरो, मंडी। मंडी में सरदार पटेल विद्युतविद्यालय द्वारा शहीदों दिवस पर 'अमर बलिदानों: इतिहास के प्रेरणास्रोत' विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम माण्डव्य छात्र अध्ययन मंडल व इतिहास एवं भौतिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शोधार्थी और प्राध्यापक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति ललित कुमार अवस्थी और अध्यक्ष कुलसचिव शशि पाल नेगी रहे। मुख्य वक्ता प्रो वीर सिंह रांगड़ा, भौतिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश विद्युतविद्यालय शिमला ने शहीदों के बलिदान और इतिहास से प्रेरणा लेने पर प्रकाश डाला। इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रा. राजेश शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। कुलसचिव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारे गौरवशाली इतिहास को याद करने और प्रेरणा लेने का अवसर हैं।

शहीदी दिवस पर भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि

अनंत ज्ञान, श्री राम हनुमान मंदिर प्रांगण में देश के वीर सपूत शहीद-ए-अजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान समाजसेवी स्वामी राणा ने बताया कि शहीद भगत सिंह कमिटी द्वारा ग्राम पंचायत महादेव के पूर्व प्रधान पदम सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपस्थित लोगों ने शहीदों की तस्वीरों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की और नतमस्तक होकर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में कमिटी के प्रधान वैदेद ठाकुर, सचिव विदेद ठाकुर और मिलाप सिपाहिया सहित कई गणजन्य लोग मौजूद रहे।

छाणंग स्कूल में बच्चों ने लगाए गोल्डन रेन के पौधे

अनंत ज्ञान ब्यूरो, मंडी। मंडी जिले के शिक्षा खंड दंग-1 की राजकीय प्राथमिक पाठशाला छाणंग में बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण की अजूबी मिसाल पेश की। स्कूल प्रबंधन समिति की पहल पर वन विभाग की हराबाग नर्सरी से लाए गए गोल्डन रेन के 20 पौधे सोमवार को बच्चों ने शिक्षक प्यार चंद सकलानी के नेतृत्व में स्कूल परिसर में रोपे। इससे पहले श्री छाणंग-छाणंग में शिबिर लगे कृषियों ने लगाए थे। शिक्षक सकलानी ने बताया कि गोल्डन रेन के पौधे छायादार होने के साथ सुंदर फूलों से जापानवरण को महकते हैं, जिससे बच्चों को गर्मी में ठंडी छाया मिलेगी। उन्होंने पौधे उपलब्ध करवाने के लिए वनरक्षक सजना ठाकुर और वन विभाग का आभार जताया। इस अवसर पर स्कूल प्रभारी शंकरदेव, योगराज और एसएमसी सदस्य निशा ठाकुर भी उपस्थित रहे।

मंडी में सीजीएएस वेलनेस सेंटर को मंजूरी

अनंत ज्ञान, सरकाघाट। केंद्र सरकार ने मंडी में लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए सीजीएएस वेलनेस सेंटर खोलने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से सेवानिवृत्त पेशेवर डॉ. कर्मियों, अधिकारियों और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। यह सुविधा मिल्न से मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों के हजारों लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी और उन्हें दूरदराज इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। संगठन के प्रदेश महासचिव ज्ञान ठाकुर और मीडिया प्रभारी विजय ठाकुर ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सांसद कंगना खलत सहित केंद्र सरकार का आभार जताया। सेवानिवृत्त कर्मियों के बलबल सिंह सख्त सहित कई सदस्यों ने फैसले का स्वागत किया।

विकलांगों ने मांगी एक समान पेंशन

अनंत ज्ञान, मंडी। हिमालयन दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष हेमरत्ना पाठनियों की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के बाद जिला सचिव भारती राणा द्वारा जारी विज्ञापन में मांग की गई है कि सभी दिव्यांगों को एक समान पेंशन प्रदान की जाए। दूसरे प्रस्ताव में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की लिफ्ट को सुचारु रूप से चलने की मांग की गई है। लिफ्ट के बंद रहते दिव्यांग व वृद्ध जनों को आर्य समस्या का निराकरण करने की मांग की गई है। एक अन्य प्रस्ताव में हिमाचल प्रदेश में भी हिम बस कार्ड की जगह पूरे देश की तरह यूडीआईडी कार्ड को ही मान्यता प्रदान करने की मांग की गई है। इसके अलावा उपायुक्त कार्यालय परिसर में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए शौचालय बनाने की मांग की गई है।

कराटे, जूडो व किक् बॉक्सिंग में किया अभ्यास

अनंत ज्ञान, सरकाघाट। सरकाघाट में 18 मार्च से 22 मार्च तक एमआईएसएफ का फाउंडेशन द्वारा मार्शल आर्ट अकेडमी में पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कराटे, जूडो, वूडू और किक्बॉक्सिंग की विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 18 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नेताजी सुभाष नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से प्रमाणित वूडू कोच रोहित राणा और अंतरराष्ट्रीय किक्बॉक्सिंग रेफरी मोहित राणा ने प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शन किया। समापन समारोह में वरिष्ठ अधिकृत अरुण कुमार मुख्य अतिथि रहे। पुरुष वर्ग में जैस, सब-जुनियर में प्रणव चौहान और महिला वर्ग में राधिका शर्मा को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु चुना गया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मोमेटो प्रदान किए गए। अकेडमी युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा विकसित करने का मंच प्रदान करती रही है।

सुखरू के बजट प्रस्तावों पर बिफरे महाविद्यालय शिक्षक

अनंत ज्ञान

मंडी। राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में 3 प्रतिशत कटौती/स्थगन के निर्णय का कड़ा विरोध किया है और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। संघ की ओर से प्रदेशाध्यक्ष बनिता सकलानी द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है कि यदि सरकार यह निर्णय वापस नहीं लेती, तो महाविद्यालय शिक्षक अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। संघ का कहना है कि छह माह के लिए किया गया यह अस्थायी कदम राज्य की वित्तीय स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं लाएगा और इसके बजाय दीर्घकालिक और प्रभावी उपायों पर ध्यान देना चाहिए।

संघ ने सरकार की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 17 वर्षों से महाविद्यालय केंद्र के शिक्षकों को करिअर एडवांसमेंट स्कीम का कोई लाभ नहीं मिला है। इसके साथ ही कर्मचारियों को महंगाई भता भी नहीं दिया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और प्रभावित हुई है। संघ ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण और कर्मचारी विरोधी बताया और चेतावनी दी कि इस प्रकार के कदम भविष्य में कर्मचारियों पर दबाव डालने की गलत परंपरा स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा, संघ ने उच्च शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना में शिक्षकों की भर्ती और उनके वेतन का प्रबंध स्पष्ट नहीं है। कुछ महाविद्यालयों में बी.वाक कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव भी ठीक नहीं है, जबकि बीएड कोर्स पर विचार किया जाना चाहिए। संघ ने सरकार से अपील की है कि निर्णय तुरंत वापस लिया जाए और संबंधित पक्षों के साथ सार्थक संवाद स्थापित किया जाए, अन्यथा शिक्षक समुदाय लोकतांत्रिक आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होगा।

मंडी में भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक की तैयारियां तेज

अनंत ज्ञान ब्यूरो, मंडी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक मंडी में आयोजित करने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। व्यवस्थाओं के लिए आयोजित बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि यह बैठक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के उद्देश्य से नियमित होती है। इस बार मुख्य बैठक 7 तारीख को होगी, जबकि 5 तारीख की रात से छोटी टोली बैठकों का दौर शुरू होगा। प्रदेश स्तर की इस बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी भाग लेकर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा करेगी। बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श कर जिम्मेदारियों सौंपी जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने कहा कि मंडी के लिए यह गौरव की बात है और कार्यकर्ता प्रदेश भर से आने वाले पदाधिकारियों का स्वागत कर सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में भाजपा प्रदेश सचिव प्रियंता शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा सहित जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

व्यास नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू व शव निकालने का किया अभ्यास



व्यास नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालते हुए। **अनंत ज्ञान**

अनंत ज्ञान

पंडोह। पंडोह में बीबीएमबी डैम में सोमवार को व्यापक स्तर पर मांस ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें फ्लैश फ्लड जैसी आपात स्थिति का अभ्यास किया गया। इस दौरान व्यास नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और नदी से शवों को रेस्क्यू करने के अभ्यास किए गए।

ड्रिल का आयोजन सीआईएसएफ व बीबीएमबी के संयुक्त तत्वावधान में हुआ, जिसमें डीडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पंडोह पुलिस और बीबीएमबी अस्पताल के लगभग 140 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। ड्रिल के दौरान सभी टीमों ने समन्वय के साथ बचाव कार्य सफलतापूर्वक किए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कमांडरों के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया।

सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट विशाल बंसल ने बताया कि बरसात के मौसम में फ्लैश फ्लड की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इस तरह के अभ्यास समय पर रहते और बचाव सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। सभी विभागों के अधिकारियों को समापन के अवसर पर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।

देवधुन संग सुकेत देवता मेले का आगाज

180 साल बाद देव नाग चासी सिद्ध की मौजूदगी से ऐतिहासिक बना मेला, आस्था में डूबा सुंदरनगर

अनंत ज्ञान

उमेश भारद्वाज, सुंदरनगर। सुकेत राज्यस्तरीय सुकेत देवता मेला-2026 का शुभारंभ सोमवार को जवाहर पार्क में पारंपरिक देवधुन के साथ भव्य रूप से हुआ। आस्था और संस्कृति के इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर हिमाचल पर्यटन विभाग के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने मुखातिबों के रूप में शिरकत की। जबकि उनके साथ पूर्व सीपीएस सोहनलाल ठाकुर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरनगर की ऐतिहासिक शुक्देव वाटिका में देवी-देवताओं की विधिवत पूजा-अर्चना से हुई। इसके बाद जवाहर पार्क तक भव्य जलेब निकाली गई, जिसमें पारंपरिक वाद्ययंत्रों और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस जलेब में देव श्री मूलू माहानाग, बड़ोदेव कम्बरनाग, देव महासु, देव बड़ोयोगी, देवी कामाक्षा जैदेवी सहित कई प्रमुख देवी-देवता शामिल हुए। खास बात यह रही कि लगभग 180



सुकेत देवता मेला पूजन के साथ शुरू। **अनंत ज्ञान**

प्रगति पर शिव धाम का काम, 33 करोड़ रुपए का हुआ टेंडर

रघुवीर सिंह बाली ने मंडी के निर्माणधीन 'शिव धाम' को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि 33 करोड़ का टेंडर हो चुका है और कार्य प्रगति पर है। इस दौरान उन्होंने मंडी जिला में अधूरे पड़े पर्यटन होटलों को लेकर पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एशियाई विकास बैंक के तहत करोड़ों रुपए की लागत से कई होटल बनाए गए थे, लेकिन उचित प्रबंधन और सफा विजन के अभाव में वे पिछले पांच वर्षों से चालू नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि कई संपत्तियां न्यायिक प्रक्रिया में फंसी हुई थीं या अन्य विभागों को स्थानांतरित कर दी गई थीं, जिन्हें अब पर्यटन निगम द्वारा वापस लेकर पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में पर्यटन निगम का टर्नओवर 78 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुराने और ऐतिहासिक होटलों के नवनीकरण के लिए इस वर्ष के बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वर्षों के लंबे अंतराल के बाद गढ़पट्टि देव नाग चासी सिद्ध की भी पावन उपस्थिति ने इस आयोजन को और अधिक ऐतिहासिक बना दिया। इस मौके पर रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि सुकेत की यह पावन धरती प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की जीवंत पहचान है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए प्रशासन व जनता को बधाई दी।

पंचायत चुनावों के दौरान गांव-गांव चलेगा चिट्ठा मुक्त अभियान: वीना



डॉ. वीना राठौर बैठक की अध्यक्षता करती हुईं। **अनंत ज्ञान**

अनंत ज्ञान, मंडी। मंडी में हिमाचल किसान यूनियन ने प्रदेश सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सीता राम वर्मा, राज्य महासचिव रोशन लाल शर्मा और जिला प्रधानों ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि पिछले 25 वर्षों के बजट प्रावधानों की तुलना में यह बजट सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद सिंह सुखरू ने किसानों की लंबे समय से चली आ रही किसान आयोग गठन की मांग को पूरा कर बड़ी राहत दी है। यूनियन के अनुसार बजट में खेत बाड़बंदी योजना के लिए 10 करोड़ रुपये, प्राकृतिक खेती उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, दूध के दाम में 10 रुपये की बढ़ोतरी, अदरक पर पहली बार एमएसपी, हल्दी का समर्थन मूल्य 150 रुपये करना और पशुपालकों के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। यूनियन ने कहा कि यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

लिफ्ट प्रतिबंध हटें। यह अभियान 15 अप्रैल, हिमाचल दिवस से शुरू होकर मतदान तक जारी रहेगा। जिन गांवों को बाड़ सम्मेलन नहीं हुए हैं, उन्हें 5 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। साथ ही अग्रैल के दूसरे पखवाड़े में महिलाओं स्कूली बच्चों व शिक्षकों के लिए नश मुक्ति पर कार्यशालाएं आयोजित होंगी।

समिति ने चिट्ठा तस्वीरों में पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स से स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर श्रमिकों को भत्ता नहीं दिया गया तो सभी कामगारों के साथ मिलकर बीडीओ कार्यालय बालीचौकी का घेराव किया जाएगा।

इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में महेंद्र सिंह राणा के अलावा देवेंद्र कुमार, इंंदर सिंह, अमर सिंह, नेत्र कुमार, चमन लाल, दबे राम, पदम देव, लाल सिंह, लिलक राज और नारायण सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे।

43 दिन से काम न मिलने पर श्रमिकों में रोष



बालीचौकी में सेमिनार के बाद मांग करते हुए। **अनंत ज्ञान**

नूतन ठाकुर, बालीचौकी। उपमंडल में सोमवार को भगत सिंह शहीदी दिवस के अवसर पर हिमाचल किसान सभा द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस दौरान सबसे पहले एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने शहीदों के विचारों और वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की।

सेमिनार को किसान सभा के राज्य कमिटी सदस्य महेंद्र सिंह राणा ने संबोधित करते हुए कहा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा कि भगत सिंह समाजवाद आधारित व्यवस्था और शोषणमुक्त समाज के पक्षधर थे। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए कहा कि आजादी के दशकों बाद भी देश की नीतियां साम्राज्यवादी प्रभाव में बन रही हैं। अमेरिका के दबाव में मनोरणा के तहत काम न मिलने पर बेरोजगारी भते की मांग उठाई। बताया गया कि 10 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत थाटा में श्रमिकों ने काम के लिए आवेदन किया था, लेकिन 43 दिन बीत जाने के बाद

सावाज्यवाद विरोधी दिवस पर नीतियों को लेकर उठाए सवाल

वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए कहा कि आजादी के दशकों बाद भी देश की नीतियां साम्राज्यवादी प्रभाव में बन रही हैं। अमेरिका के दबाव में मनोरणा के तहत काम न मिलने पर बेरोजगारी भते की मांग उठाई। बताया गया कि 10 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत थाटा में श्रमिकों ने काम के लिए आवेदन किया था, लेकिन 43 दिन बीत जाने के बाद

